

आखिरकार १४ संशोधनों के साथ वक्फ बोर्ड संशोधित विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी!



नई दिल्ली, २७ फरवरी (वृत्तसंस्था) वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा जारी थी। बजट सत्र के पहले चरण में यह विधेयक संसद में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया।

१४ संशोधनों के साथ केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

संसदीय समिति द्वारा सुझाई गई ४४ सिफारिशों को नामंजूर कर दिया गया, जबकि १४ सिफारिशों को संशोधन के लिए स्वीकार किया गया। अब इन १४ संशोधनों के साथ वक्फ बोर्ड विधेयक के संशोधित मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

अब बजट सत्र के दूसरे चरण में यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा

और इसे अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें

संयुक्त संसदीय समिति में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (छऊ-) के सदस्यों ने कुल १४ सिफारिशें दी थीं, जबकि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के सदस्यों ने ४४ बदलाव सुझाए थे।

हालांकि, विपक्ष द्वारा सुझाई गई सभी ४४ सिफारिशें खारिज कर दी गईं, जबकि सत्तारूढ़ छऊ- के १४ संशोधनों को मंजूरी मिल गई।

२७ जनवरी २०२५ को संयुक्त संसदीय समिति ने इन संशोधनों को मंजूरी दी थी, और अब केंद्रीय कैबिनेट ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है।

१० मार्च से संसद में पेश होगा संशोधित विधेयक बजट सत्र का दूसरा

चरण १० मार्च से शुरू हो रहा है, और उसी दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

मुख्य तीन संशोधन स्वीकृत १४ संशोधनों में तीन प्रमुख बदलाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं:

१. वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को वेबसाइट पर दर्ज करने की छह महीने की समयसीमा में छूट।

२. संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या सरकार की - यह तय करने का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को सौंपा जाएगा।

३. मुस्लिम कानून और सिद्धांतों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की वक्फ ट्रिब्यूनल (लवाद) में नियुक्ति।

भाजपा को विधेयक पारित होने का भरोसा संसद में सत्तारूढ़ दल की स्थिति और वोटों के गणित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूरा भरोसा है कि यह विधेयक पारित हो जाएगा। लोकसभा में भाजपा के २४० सांसद हैं। तेलुगु देशम पार्टी के १६ सांसद और जदयू (गऊ) के १२ सांसद भी विधेयक के समर्थन में वोट डालेंगे। इसके अलावा, लोक जनशक्ति पार्टी (झण्डा) के ५ सांसदों के वोट भी अहम होंगे। राष्ट्रीय लोक दल (ठडऊ) के २, जनता दल सेक्युलर (गऊड) के २ और अपना दल के १ सांसद भी विधेयक का समर्थन करेंगे। भाजपा के पास संख्याबल होने के कारण यह विधेयक आसानी से पारित होने की संभावना जताई जा रही है।

वक्फ बोर्ड के छह विभागीय कार्यालय जल्द होंगे शुरू!

गतिशील कार्यप्रणाली के लिए ४ उपमुख्य कार्यकारी पदों को मंजूरी

औरंगाबाद (प्रतिनिधि), २७ फरवरी - महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव लाने और लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब कामकाज में तेजी लाने के लिए छह विभागीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे, साथ ही चार नए उपमुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पदों को भी मंजूरी दी गई है। यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष समीर गुलाम नबी काज़ी ने दी।

वक्फ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए निर्णय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता समीर काज़ी ने की। इस दौरान वरिष्ठ सदस्य मौलाना अथर अली, हसनैन शाकिर, ए.यू. पठान, सैयद इफ्तेखार हाशमी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सैयद और उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मुशिर शेख उपस्थित थे।

अध्यक्ष समीर काज़ी ने बताया कि वक्फ नौदणी, संस्था सदस्यता परिवर्तन और नई संस्था समिति की स्थापना से संबंधित

मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महीने के भीतर विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। अब जिला स्तर पर वक्फ से जुड़े मामलों में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए जिला वक्फ अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। ६ विभागीय कार्यालयों से जनता को मिलेगा लाभ छह विभागीय कार्यालय शुरू होने से लोगों को अपने क्षेत्र में ही आसानी से काम निपटाने की सुविधा मिलेगी। मुख्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभागीय स्तर पर अधिकारियों को अधिक अधिकार सौंपे जाएंगे ताकि समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सके। इससे जनता का समय और पैसा दोनों बचेंगे। २८९ संबंधित मामलों को मिली मंजूरी बैठक में संस्थाओं से संबंधित २८९ मामलों, समितियों के ४९ मामलों और बदलाव से जुड़े ३० मामलों का निपटारा किया गया। गौरतलब है कि पिछले एक साल में बोर्ड ने कुल १,००१ मामलों को मंजूरी दी है, जो वक्फ बोर्ड के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष

समीर काज़ी का बयान

गतिशील प्रशासनिक कार्यप्रणाली अपनाने का हमारा

संकल्प है और पिछले वर्षभर में हमने इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। लोकसेवा को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य में छह विभागीय कार्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया है। चार नए उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे कार्यों का विभाजन सुचारु रूप से किया जा सकेगा।

हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि जनता को मौके पर ही त्वरित न्याय मिले और किसी को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। आने वाले समय में जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक सुधार किए जाएंगे। - समीर काज़ी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड।

छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली विचारधारा को खत्म करना जरूरी: हर्षवर्धन सपकाल

राज्य सरकार की नीति-‘अपमान करो और इनाम व संरक्षण पाओ’

महिलाओं पर बढ़ते अपराध सरकार की विफलता, गृह विभाग की कार्यशैली ‘घाशीराम कोतवाल’ जैसी



रायगढ़/मुंबई, २७ फरवरी - हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को नकारने वाले और उनके खिलाफ गलत प्रचार करने वाली विचारधारा आज भी जीवित है। दुख की बात यह है कि शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है, उन्हें इनाम और सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन हम ऐसी सोच को ‘टकमक टोक’ से खत्म करने का संकल्प लेते हैं, यह बात महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कही।

(‘टकमक टोक’ रायगढ़ किले की एक खड़ी पहाड़ी चोटी है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में अपराधियों और गद्दारों को सजा के तौर पर खाई में फेंक दिया जाता था, ताकि उनका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाए।)

शिवाजी महाराज और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आज रायगढ़ किले पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर महाड़ में चवदार तालाब का दौरा कर भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को नमन किया।

‘जो महाराज का अपमान करे, उसे सुरक्षा और पुरस्कार’

हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि एक अभिनेता ने शिवाजी महाराज का अपमान किया, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय उसके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी।

इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जबकि दूसरी ओर शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान करने वाले सावकर को सरकार सम्मानित कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

‘सरकार हिंदवी स्वराज्य के सिद्धांतों को भटका रही’

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था, बल्कि एक नए शासन की कल्पना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद लागू संविधान में भी हिंदवी स्वराज्य का विचार समाहित है और कांग्रेस की नीतियां भी इसी स्वराज्य के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं।

रायगढ़ पहुंचने का उद्देश्य यही है कि हम महाराज के सपनों के अनुसार जनता की सरकार स्थापित करेंगे।

‘महिलाओं पर बढ़ते अपराध सरकार की नाकामी का प्रमाण’

पुणे में हाल ही में हुई दुष्कर्म की घटना पर बोलते हुए हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध सरकार की विफलता का प्रमाण हैं।

गृह विभाग की कार्यशैली ‘घाशीराम कोतवाल’ जैसी बन गई है, जहां आम जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है।

क्या आज भी वही हो रहा है, जो पेशवाओं के समय हुआ था? जब शिवाजी महाराज ने सत्ता सौंपी, लेकिन बाद में पेशवाओं ने हिंदवी स्वराज्य को नुकसान पहुंचाया।

‘पद्मश्री डॉ. हेमतराव बावसकर से भेंट’ महाड़ में सांप के जहर पर शोध कर प्रभावी दवा तैयार करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री डॉ. हेमतराव बावसकर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने उनके परिवार से भी चर्चा की।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अनुर लोंढे, रायगढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र घरत, प्रदेश कांग्रेस महासचिव व रायगढ़ जिला प्रभारी श्रीरंग बगें, कांग्रेस की अधिवक्ता श्रद्धा ठाकुर, युवक कांग्रेस अध्यक्ष हेमराज महातर, वरिष्ठ नेता आरसी घरत, दिलीप पाडांगकर समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे।

वाल्मिक कराड समेत ८ आरोपियों के खिलाफ सीआयडी दाखिल करेगी १४०० पन्नों की चार्जशीट



बीड, २७ फरवरी (प्रतिनिधि) सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में सरकार ने विशेष सरकारी वकील के रूप में उज्ज्वल निकम की नियुक्ति के बाद जांच में तेजी आ गई है। अब इस मामले में बड़ी खबर सामने आई है।

सूत्रों के मुताबिक, उखऊ आज वाल्मिक कराड समेत ८ आरोपियों के खिलाफ १४०० पन्नों की चार्जशीट दाखिल करेगी। बीड के विशेष मकोका कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

अपहरण और हत्या से जुड़े

खुलासे होंगे ९ दिसंबर २०२४ को सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया था कि

आवादा कंपनी से मांगी गई रंगदारी (फिरोती) के विवाद के कारण यह हत्या की गई।

उखऊ इस मामले की जांच कर रही थी, जिसमें रंगदारी से लेकर अपहरण तक के सभी पहलुओं की छानबीन की गई। जबकि हत्या की जांच उखई (डिटैक्शन क्राइम ब्रांच) को सौंपी गई थी।

अब उखऊ की १४०० पन्नों की चार्जशीट में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है।

इन ८ आरोपियों के खिलाफ होगी चार्जशीट

उखऊ की इस चार्जशीट में वाल्मिक कराड, विष्णु चाटे, सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, जयराज चाटे, कृष्णा आंधळे, सुधीर सांगळे और सिद्धार्थ सोनवणे के खिलाफ सबूत और उनके अपराध में संलिप्तता के विवरण शामिल होंगे।

विशेष मकोका कोर्ट में पेश की जाने वाली चार्जशीट में इन अहम बिंदुओं का खुलासा होने की संभावना है: रंगदारी प्रकरण में मुख्य साजिशकर्ता कौन था? आरोपियों को फरार होने में किसने मदद की? आरोपियों को आर्थिक सहायता कहां से मिली? गवाहों के बयान और अन्य सबूतों का विवरण। सरकार ने विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने २६ फरवरी को इस मामले में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया है, जबकि डॉ. बाळासाहेब कोल्हे को सहायक विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। देशमुख परिवार की एक मांग पूरी हुई

संतोष देशमुख के परिवार ने सरकार के सामने सात मांगें रखी थीं, जिनमें से एक मांग पूरी हो गई है। अब यह देखना अहम होगा कि उखऊ की चार्जशीट में किन नए तथ्यों का खुलासा होता है और आगे की कानूनी कार्रवाई किस दिशा में जाती है।

राजनी पाटिल आजसे शिमला दौरे पर, एचपीसीसी पुनर्गठन की प्रक्रिया होगी तेज

शिमला, २७ फरवरी (तामीर न्यूज सर्विस) - अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजनी पाटिल २८ फरवरी को पहली बार शिमला का दौरा करेंगी। दो दिवसीय दौरे के दौरान, वे कांग्रेस नेताओं, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों से मिलेंगी ताकि

भंग हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। बैठकों का सिलसिला: २८ फरवरी को राजनी पाटिल -खउउ के राज्य सचिवों के साथ बैठक करेंगी। वे पूर्व वक्खउउ अध्यक्षों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधानसभा अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगी।

शाम को वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री, वक्खउउ अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सभी कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करेंगी।

दूसरे दिन का कार्यक्रम: अपने दौरे के दूसरे दिन, वे विधानसभा चुनाव २०२२ में असफल रहे कांग्रेस उम्मीदवारों और विभिन्न मोर्चा संगठनों एवं विभागों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी।

गौरतलब है कि -खउउ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने तीन महीने पहले वक्खउउ को भंग दिया था। इसके पुनर्गठन में हो रही

देरी से पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज हैं, जिनमें कृषि मंत्री चंदर कुमार और स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल शामिल हैं।

ग्रासरूट स्तर पर रायशुमारी: पहली बार, हिमाचल प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने १६ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी, ताकि वे ब्लॉक और जिला समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए जमीनी स्तर से फीडबैक एकत्र कर सकें।

हालांकि, स्थानीय नेताओं का मानना है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट नई नेतृत्व व्यवस्था में अधिक प्रभावी नहीं होगी। पार्टी

नेताओं में असंतोष: पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से अधिकांश पार्टी नेताओं में नाराजगी देखी गई। कई नेताओं ने इसे अधिकारों में हस्तक्षेप बताया, खासकर वक्खउउ अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसे नकारात्मक रूप से लिया। नए वक्खउउ अध्यक्ष की तलाश: इसके अलावा, राजनी पाटिल और पार्टी हाईकमान को वक्खउउ के नए अध्यक्ष के चयन पर फैसला लेना होगा।

प्रतिभा सिंह का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है और अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें फिर से नियुक्त किया जाएगा या नहीं।

विभिन्न संभावित उम्मीदवारों के नाम चर्चा में हैं, जिनमें एक पूर्व वक्खउउ अध्यक्ष और एक पूर्व मुख्य संसदीय सचिव प्रमुख हैं।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और वित्तीय सहायता दरें कम करने की मांग-मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई, २७ फरवरी (विशेष प्रतिनिधि) - नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, विद्युत ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणाली पर निर्णय लेने, बिजली वितरण क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (–ख) और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने, स्मार्ट मीटर लगाने तथा केंद्र सरकार के अधीन अन्य ऊर्जा संबंधित विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर समाधान निकाला जाएगा, यह बात केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाइक ने गुरुवार को कही।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उदय योजना को पुनः लागू करने, वित्तीय सहायता दरों को कम करने, अतिरिक्त लेवी को रद्द करने, और महावितरण को ब्याज मुक्त बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने की मांग की।

ऊर्जा मंत्री समूह की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

सह्याद्री अतिथिगृह में बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता और अन्य ऊर्जा संबंधी मुद्दों को लेकर ऊर्जा मंत्री समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाइक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री वी. सेंथिल बालाजी, मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, आंध्रप्रदेश के ऊर्जा मंत्री गोडूपत्ती रविकुमार, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हिरालाल नागर, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, और महाराष्ट्र की ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर उपस्थित थे।

केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाइक ने बताया कि वर्ष २०२३-२४ की रिपोर्ट के अनुसार, देश के ऊर्जा क्षेत्र में कुल १६.२८% घाटा हुआ है। इस नुकसान को कम करने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश और गुजरात को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

ऊर्जा क्षेत्र के सुधार के लिए सुझाव बिजली वितरण कार्यों में –ख और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। सरकारी विभाग समय पर बिजली बिलों का भुगतान करें। राज्य विद्युत नियामक आयोग (डिएड) बिजली दरों की समय-समय पर समीक्षा करें।

स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली की हानि को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। समय आधारित बिजली दरों को लागू किया जाए। ऋण पुनर्गठन और वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों से धन एकत्र किया जाए। इस विषय पर अगली बैठक उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी। महावितरण की

वित्तीय स्थिरता के लिए राज्य सरकार के प्रयास - मुख्यमंत्री फडणवीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महावितरण देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत २८% है, जो देश में सबसे अधिक है। महावितरण का कुल राजस्व १.१२ लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से ४९% उद्योगों से आता है। उन्होंने बताया कि महावितरण की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार लगातार उपाय कर रही है। 'मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना' के तहत सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जिससे बिजली वितरण में हानि कम होगी और बिजली दरों में कमी आएगी। इससे बचाई गई रकम से आम उपभोक्ताओं और उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कदम बड़े पैमाने पर किसानों को सौर कृषि पंप दिए जा रहे हैं, जिससे दिन के समय बिजली मिल सके। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से लाभ उठाते हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी घरों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। ३० लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आएगा। नवीकरणीय ऊर्जा को ५२% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (–ख) और स्मार्ट तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी उपायों से महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और बिजली वितरण को अधिक प्रभावी और किफायती बनाने में मदद मिलेगी।

मुंबई क्राइम ब्रांच की ऐतिहासिक इमारत के स्थान पर बनेगा हाई-टेक कमांड कंट्रोल सेंटर

११९ साल पुरानी इमारत के पुनर्विकास पर खर्च होंगे ६० करोड़ रुपये!

मुंबई, २७ फरवरी (विशेष समाचार, जमीर काजी) - मुंबई क्राइम ब्रांच की ११९ साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत, जहां २६/११ आतंकी अजमल कसाब से लेकर कई कुख्यात गैंगस्टर्स को रखा गया था, अब जल्द ही पुनर्विकास के तहत हाई-टेक कमांड और कंट्रोल सेंटर में तब्दील होगी। यह अत्याधुनिक पांच मंजिला भवन होगा, जिसके निर्माण पर ६० करोड़ रुपये की लागत आएगी। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा।

इतिहास से जुड़ी क्राइम ब्रांच की इमारत १९०६ में बनी यह इमारत मुंबई पुलिस आयुक्तालय परिसर के भीतर स्थित है। यहां हाजी मस्तान, याकूब लाला, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली गैंग से जुड़े अपराधियों, १९९३ मुंबई बम धमाकों के आरोपी, और मुंबई दंगों से जुड़े कई गैंगस्टर्स को रखा गया था।

२६/११ मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए अजमल कसाब से भी इसी इमारत में पूछताछ हुई थी। वर्तमान में, इस इमारत में अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय स्थित हैं। हालांकि, इमारत अब अत्यधिक जर्जर हो चुकी है और इसे बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है।

नई इमारत में होगा अत्याधुनिक सुरक्षा नियंत्रण केंद्र

मुंबई एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है, जहां जनसंख्या घनत्व अत्यधिक अधिक है। इसके चलते सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बेहतर निगरानी रखना आवश्यक हो गया है।

फिलहाल मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय की पांचवीं मंजिल पर स्थित मौजूदा नियंत्रण केंद्र में सिर्फ २०

अत्याधुनिक कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा।

३. तीसरे, चौथे और पांचवें तल पर अपराध शाखा का प्रशासनिक कार्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लाउंज होंगे।

हाई-टेक कंट्रोल सेंटर से सुरक्षा होगी और मजबूत

२४घंटा अपराध निगरानी के लिए अत्याधुनिक कमांड सेंटर होगा।

दो वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम और सरकारी अधिकारियों के साथ सुरक्षित संचार सुविधा होगी।

डेटा स्टोरेज और बैकअप के लिए हाई-टेक सर्वर और ग्लाइड पावर बैकअप जेनरेटर लगाए जाएंगे।

–ख (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित निगरानी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा।

झाखण (पिक्चर इंटेलिजेंस यूनिट) लैब स्थापित की जाएगी, जिससे अपराध रोकथाम में तेजी आएगी।

६० करोड़ रुपये होंगे खर्च, बजट में होगा प्रावधान

मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। १० मार्च को पेश होने वाले नए बजट में ६० करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, मुंबई पुलिस द्वारा इस हाई-टेक सेंटर को जल्द से जल्द शुरू करने की योजना बनाई जा रही है ताकि महानगर की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

सर सैयद अहमद खान और पीपल्स माध्यमिक स्कूल के छात्र रासेक अनस ने यूनिक बेसिक कंप्यूटर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया

हमजा खालिद को दूसरा पुरस्कार (टैब) और उमर नदीम को तीसरा पुरस्कार (साइकिल) मिला

बीड, २७ फरवरी - सर सैयद अहमद खान और पीपल्स माध्यमिक स्कूल छात्रों में नए कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न विषयों का शिक्षण कराता है। पिछले २० वर्षों से इस स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। आधुनिक युग में तकनीक और कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक हो गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिक बेसिक कंप्यूटर ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सर सैयद अहमद खान और पीपल्स माध्यमिक स्कूल के ९५ छात्रों ने भाग लिया। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और छठा पुरस्कार इसी स्कूल विजेताओं को सम्मानित किया गया

आज मुख्य अतिथियों के हाथों विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

प्रतियोगिता में विजयी छात्र: प्रथम पुरस्कार (कंप्यूटर) - शेख रासेक अनस वासेक

द्वितीय पुरस्कार (टैब) - हमजा खालिद

तृतीय पुरस्कार (स्पोर्ट्स साइकिल) - शेख उमर नदीम

छठा पुरस्कार (स्पोर्ट्स किट) - कौसर विश्वी, खमर विश्वी

इसके अलावा, तीन छात्रों को ट्रॉफी और छह छात्रों को मोटिवेशनल प्राइज मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अतिथि

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अशफाक इनामदार, काज़ी मखदूम, शेख शकील, शेख अब्खिल, पठान अजीम, मोमिन कवी (सदाम), कामरान खान और अनाम इनामदार उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन शेख रज़ी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का संचालन शेख आदिल सर ने किया और अतिथियों व छात्रों का आभार शेख रज़ी सर ने व्यक्त किया।

मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम का वर्कशॉप

मुरुड, जंजीरा (रायगढ़) और आसपास के ३०० सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों की भागीदारी

२७ फरवरी (तामीर न्यूज़) - महाराष्ट्र सरकार के वित्तीय संस्थान मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम ने मुरुड (जिला रायगढ़) के वसंतराव नाइक कॉलेज के सभागार में एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और कॉलेज के छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

वर्कशॉप में मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के अध्यक्ष मुस्ताक अंतुले, प्रबंध निदेशक गणकार मखदूम, निदेशक अहमद शरीफ़ देशमुख और मुंबई कार्यालय के अधिकारी मौजूद थे। शिक्षा एवं व्यवसाय ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को कहा कि कोंकण सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी इस तरह के वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को सरल प्रक्रिया के तहत ऋण मंजूर कराया जा सके। सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों की भागीदारी

इस वर्कशॉप में इस्माइल घोले, डॉ. मुस्ताक मकदूम, अदीब मल्लाख, मुफ्ती नज़ीर अहमद, गुलाम चिरफ़े, मुजीब परकार, अब्दुल शकूर, फज़ल हलदे, इरफ़ान हलदे समेत कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वित्तीय योजनाओं की जानकारी ली और विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में सभी योजनाओं से संबंधित विस्तृत ब्रोशर भी वितरित किए गए ताकि लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

CHANGE IN NAME

Old Name
SHAIKH SALMAN LAVEEQ
NEW NAME
SHAIKH SALMAN SHAIKH LAIQ
ADD: BUNDAL PURA, BEED

Urgent Need for Export

दुबई और दम्माम (सऊदी अरब) के लिए थॉमसन क्वालिटी अंगूर और गणेश या भगवा क्वालिटी अनार की आवश्यकता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल रखने वाले सप्लायर या किसान संपर्क करें।



Tameer Export: MO: 9270574444

SAPNA TRAVELS

Heavy Parcel Booking
9960828578 / 9156333999

Beed Office
9075868000
7058575575

Online Booking

redBus

www.redbus.in

Paytm

Beed to Mumbai (panvel-sion-borivali)

Beed to Pune (bhosari-nigdi)

Shivaji Chowk, Near Mahindra showroom, Beed-431122